

दिनांक 04 अप्रैल, 2007 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत  
सचिव समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04.04.2007 को अपरान्ह 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री इन्दु कुमार पाण्डे, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एन0एस0 नपलच्याल, प्रमुख सचिव, राजस्व, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती विनीता कुमार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एन0रवि शंकर, प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री डी0के0 कोटिया, सचिव, सूचना एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री पी0के0 महान्ति, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री एस0एस0 सन्धु, सचिव, पेयजल एवं पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, महिला सशक्तीकरण, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री एस0के0 माहेश्वरी, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री हरीश चन्द्र जोशी, सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग एवं प्रोटोकाल, उत्तराखण्ड शासन।
12. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
13. श्री पी0एस0 जंगपागी, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

- 1- स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस बार स्थानान्तरण नीति में कई नये बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है। इन बिन्दुओं में दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर Incentives दिया जाना, स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध स्थानों एवं प्रक्रिया आदि का इन्टरनेट पर प्रकाशन, स्थानान्तरण में सम्बन्धित कार्मिक की सहभागिता, प्रोन्नति में दुर्गम क्षेत्र में सेवायें प्रदान करने की अनिवार्यतायें आदि समाविष्ट की गई है।
- 2- इस नई नीति का उद्देश्य दुर्गम एवं सुगम स्थानों पर कार्मिकों की तैनाती में संतुलन बनाये रखना है।
- 3- Incentives के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिक को दो स्थानों पर आवासीय सुविधा/किराया भत्ता प्रदान करना ताकि स्थानान्तरित कार्मिक अपने दायित्वों की पूर्ति के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। 10 वर्ष से अधिक समय तक दुर्गम स्थान पर तैनाती पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान करना तथा बच्चों को शिक्षण शुल्क का अतिरिक्त भुगतान करना आदि सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि को

10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है। यह भी निर्देश दिये गये कि दुर्गम स्थान पर तैनाती के समय कार्मिक को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधायें वास्तविकता के धरातल पर सम्भव हैं या नहीं, तथा इस हेतु निहित वित्तीय उपाशय के सन्दर्भ में वित्त विभाग का भी परामर्श प्राप्त कर लिया जाय। तदुपरान्त प्रस्ताव मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाय।

4- बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि प्रथम नियुक्ति के समय एवं प्रोन्नति के समय तैनाती दुर्गम स्थान पर यथासम्भव अनिवार्य की जाय।

5- पुर्नवास नीति निर्धारण पर विचारविमर्श के दौरान मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों की फिजीविलिटी और दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ने वाली नीतियों की टिप्पणी सभी प्रमुख सचिव/सचिव को प्रचालित कर सभी विभागों के सुझाव प्राप्त कर लिये जाय तथा इसका वित्तीय दृष्टिकोण से भी परीक्षण कर लिया जाय। सभी बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षणोंपरान्त ही पुर्नवास नीति को मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा सभा के अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुये बैठक सम्पन्न की।

भवदीय  
(एस0 के दास)  
मुख्य सचिव

संख्या-236/(11)/xxxi(13)G/2007 दिनांक 17 अप्रैल, 2007 ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,  
S.A.N.  
(एस0 राजू)  
सचिव।